

**एंवागो : 29 मई, 2007 को 00:01 बजे ईडीटी; 04:00 बजे जीएमटी/यूटीसी के पहले
प्रकाशित, प्रसारित या प्रेषित न करें।**



THE WORLD BANK

Working for a World
Free of Poverty

प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति सं. 2007/58/डीईसी

संपर्क:

मेरेल टक (202)473-9516 mtuckprimdahl@worldbank.org

टी.वी.रेडियो: **सिंथिया केस** (202) 473-6287 ccase@worldbank.org

नाज़नीन आताबाकी (202) 458-1450 natabaki@worldbank.org

2006 में विकासशील देशों ने निजी पूंजी प्रवाहों में रिकार्ड वृद्धि की, पर गति अब मंद होने लगी है

वाशिंगटन डी.सी., 29 मई – 2006 में विकासशील देशों में निवल निजी पूंजी प्रवाहों की राशि ने 647 अरब डॉलर का रिकार्ड छू लिया, हालांकि इन प्रवाहों की वृद्धि दर 2005 के 34 प्रतिशत के मुकाबले 2006 में अंकित 17 प्रतिशत के साथ कुछ मंद हो गई। *वैश्विक विकास वित्त 2007* के अनुसार यूरोप के उभरते देशों ने कुल प्रवाहों का अधिकाधिक हिस्सा आकर्षित किया और ऋण की तुलना में इक्विटी आधारित वित्तपोषण का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ा। दाताओं द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, सहायता के प्रवाह निराशाजनक साबित हुए और सरकारी स्रोतों से हटकर निजी स्रोतों की ओर वित्तपोषण का स्थानांतरण जारी रहा।

विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का पूर्वानुमान है कि ब्याज की बढ़ती दरें और क्षमता में प्रतिबंध आने के कारण विकासशील देशों में गत वर्षों में जो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, उसमें कुछ मंदी आ जाएगी, और वैश्विक विकास दर 2006 के 4 प्रतिशत के मुकाबले 2009 में लगभग 3.5 प्रतिशत तक गिर जाएगी। यदि ऐसा हुआ, तो पिछले चार वर्षों में अनेक विकासशील देशों में जो समग्र सकारात्मक वित्तीय परिस्थितायां विद्यमान रही हैं, उनमें थोड़ी सुस्ती आ सकती है।

रिपोर्ट ने पाया कि 2006 में इक्विटी प्रवाहों की राशि 400 अरब डॉलर से अधिक रही, यानि कुल पूंजी प्रवाहों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा, और 2004 के दो-तिहाई हिस्से से कहीं अधिक। उभरते बाज़ारों तथा अन्य विकासशील देशों में पोर्टफ़ोलियो इक्विटी तथा प्रत्यक्ष विदेशीय निवेश (एफ़डीआई), दोनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास देखा गया। सीमा-पारीय विलयन व अधिग्रहण की लहर ने 2006 में विकासशील देशों की ओर एफ़डीआई के प्रवाहों को बढ़ावा दिया, और इस संख्या ने 325 अरब डॉलर की एक नई चोटी छू ली, जो कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर के विश्वट्यापी प्रवाहों का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।

2006 में, विकासशील देशों में स्थित निजी व सरकारी निगमों ने अभिषद् बैंक ऋणों तथा अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड निर्गमन के जरिए 333 अरब डॉलर उगाहये – यह संख्या 2002 के 88 अरब डॉलर की संख्या से कहीं

अधिक थी। क्षेत्रीय नज़र से देखा जाए तो यूरोप व मध्य एशिया के उभरते देशों की कंपनियां सामने आती हैं, और 2006 में इन्होंने 135 अरब डॉलर का ऋणविस्तार दर्शाया। वित्तीय कंपनियां, खास कर भारत, काज़ाकस्तान, रूस परिसंघ और तुर्की के बैंक, इस तथाकथित ऋण विस्फोट के अगुवे बन चुके हैं।

रिपोर्ट बताती है कि विकास वित्त एकत्रित करने के इस नए परिदृश्य – खास कर सरकारी से हटकर निजी ऋणग्राहियों की ओर जो प्रवृत्ति दिख रही है – ने जोखिम के रूढ़ीवादी आकलन को बदल दिया है, और इससे वृद्धि तथा वित्तीय स्थिरता पर भारी प्रभाव पड़ने की आशा है।

विश्व बैंक के विकास संभावनाएं समूह के निदेशक, यूरी दादुश के अनुसार "हालांकि विकासशील देशों की ओर पूंजी प्रवाहों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और ये इन देशों के सुधरते बुनियादी आंकड़ों की एक झलक प्रदान करते हैं, याद रहे कि चक्रीय कारक भी सक्रिय रहे हैं, और जैसे-जैसे विकास की गति धीमी होगी, वैसे-वैसे मजबूत देशों को भी जोरदार प्रतिवातों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे हिसाब से विमान आहिस्ता-आहिस्ता उतरेगा, पर यह हमारी सोच ही है, तथ्य नहीं।"

दृढ़ विकास तथा ऊँची पण्य कीमतों के एक अतिरिक्त वर्ष का लाभ उठाने के अलावा, निम्न आय वाले देशों द्वारा निजी ऋण बाज़ारों में प्रवेश करने की क्षमता को हाल में लाए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऋण-राहत पहलों से भी बढ़ावा मिला है जिनके फलस्वरूप इन देशों का ऋण-बोझ हल्का हो गया है और इनकी उधार-पात्रता सुधर गई है।

कुल देखा जाए तो 2006 में ऋण-बाज़ार की एक मिश्रित छवि निकलती है: हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से विदेशीय ऋणादान में काफ़ी वृद्धि हुई, बाज़ार-आधारित उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निवल बॉन्ड निर्गमन में अवनति हुई, चूँकि जिन सरकारी प्रचालन कर्ताओं के पास विदेशी मुद्रा का प्रचुर भंडार है, उन्हें बाह्य ऋणादान की कम आवश्यकता पड़ती है। देशों ने अपने-अपने बाह्य ऋण-बोझ को कम कर लिया है और अपनी बाह्य ऋण छवि को सुधार लिया है। कईयों ने अपने बकाया ऋण के बड़े हिस्सों को वापस खरीद लिया है, और विद्यमान ऋणों की परिपक्वता अवधि को बढ़ाकर, तथा शर्तों को अपने लिए अधिक अनुकूल बनाकर, इन ऋणों का फिर से वित्तपोषण कर लिया है। अल्जीरिया, नाईजीरिया और रूस जैसे कुछ खास देशों ने सरकारी ऋणदाताओं के समक्ष अपने बाह्य ऋणों को चुका दिया है। इसके परिणामस्वरूप, 2005-06 में पैरिस क्लब तथा अन्य बहुपक्षीय संस्थानों को वापस किया गया मूलधन उनके संवितरण से 146 अरब डॉलर अधिक साबित हुआ, और निवल निजी ऋण प्रवाहों की राशि 432 अरब डॉलर तक पहुँच गई।

जैसे-जैसे उभरते बाज़ारों की सरकारों ने अपना विदेशीय ऋणादान कम किया है, वैसे-वैसे निगमों ने – यानि बैंकों और कंपनियों ने – अपना ऋण बोझ बढ़ाया है।

रिपोर्ट के मुख्य लेखक, और विकास संभावनाएं समूह के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रबंधक, मंसूर दाइलामी बताते हैं कि "उभरते बाज़ारों में कंपनियां बेहद पूंजी एकत्रित कर रही हैं और वैश्विक वित्तव्यवस्था में उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती प्रतिभागिता विकासशील देशों की ओर बहने वाली पूंजी के इस चक्र का एक विशेष लक्षण बन गई है। वैश्विक पूंजी बाज़ारों तक इनकी पहुँच अब इन निगमों को वित्तपोषण के अपने स्रोतों को विविध करने का मौका दे रही है, पहले से अधिक परिष्कृत वित्तपोषण के औजारों के जरिए जोखिम

प्रबंधन में सुधार ला रही है, ऋणादान की परिपक्वता अवधि बढ़ा दे रही है, और उनके लिए पूंजी की कीमत गिरा रही है।"

पिछले कई वर्षों में जैसे-जैसे पूंजी बाजारों का एकीकरण होता गया है और विकासशील देशों से आए निगमों ने विदेश से वित्त एकत्रित करना शुरू कर दिया है, वैसे-वैसे सीमा-पारीय शेरों के आदान-प्रदान तथा प्रतिभूतियों की सूचियों में नियंत्रण लाने के लिए एक व्यापक और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण बन चुकी है। रिपोर्ट में नियंत्रणकर्ताओं तथा सरकारों से आग्रह किया जाता है कि वे लेखा-परीक्षण के मानदंडों के अंतर्गत, पारदर्शिता व गुणवत्ता पर अधिक जोर डालें। इसमें विश्वसनीय सूचनाओं के महत्व को रेखांकित किया गया है ताकि निवेशक सही व सुबोध निर्णय ले सकें और कॉर्पोरेट शासन की निष्ठा में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा की गई है।

इस बीच, वैश्विक अर्थसहायता कुछ रुक सी गई है। 2006 में 106.8 अरब डॉलर छू लेने के बाद, विकास सहायता समिति के सदस्यों की ओर से 2006 में सरकारी विकास सहायता (ओएडी) 103.8 अरब डॉलर तक गिर गई, जिससे जी-8 देशों द्वारा ग्लेनईगल्स में अफ्रीका के लिए 2010 तक विकास सहायता में वृद्धि लाने की वचनबद्धताओं पर अनिश्चितता का बादल मंडराने लगा है।

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फ्रांस्वा बुर्गिन्यों का कहना है कि "2006 में निजी पूंजी प्रवाहों का विस्तार एक ओर तो विकासशील देशों की दृढ़ता की कहानी बताती है, लेकिन चिंता की बात तो यह है कि दूसरी ओर यह प्रवृत्ति निवल सरकारी ऋणादान में गिराव तथा सहायता के लिए दी गई वचनबद्धताओं की विलंबित आपूर्ति दर्शा रही है। कई निर्धनतम देश ऐसे भी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की परिरक्षाओं पर चल रहे हैं – इनकी बुनियादी जरूरतें केवल निजी पूंजी द्वारा पूरी नहीं की जा सकती हैं।"

गत वर्षों की उल्लासभरी वित्तीय परिस्थितियों का अंशदान 2006 में विकासशील देशों द्वारा प्रदर्शित 7.3 प्रतिशत विकास दर में नज़र आता है – यह चौथा ऐसा वर्ष था जबकि विकासशील देशों ने 5.5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाई। पिछले वर्ष सभी क्षेत्रों ने कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि अंकित की: सब-सहारा अफ्रीका का प्रदर्शन 5.6 प्रतिशत रहा, दक्षिण एशिया का 8.6 प्रतिशत, मध्य-पूर्व व उत्तरी अफ्रीका का 5 प्रतिशत, लातिनी अमेरिका और कैरिबियन का 5.4 प्रतिशत, यूरोप और मध्य एशिया का 6.5, और पूर्वी एशिया व प्रशांत क्षेत्र का प्रदर्शन 9.5 प्रतिशत था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने विरले ही इतनी उल्लेखनीय व व्यापक उन्नति देखी है।

लेखकों का अनुमान है कि 2007 में यह गति कुछ धीमी होकर 6.7 प्रतिशत हो जाएगी, और 2009 में विकासशील देशों की वृद्धि 6.1 प्रतिशत की वहनीय गति अपनाने लगेगी। इस बीच, 2007 में उच्च आय वाले देशों में 2.5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। इस आंकड़े में संयुक्त राज्य अमेरिका की मंदी प्रतिबिंबित है। 2008 तथा 2009 में अमीर देशों को 2.8 प्रतिशत विकास करने की संभावना है, यदि यू.एस की अर्थव्यवस्था स्वस्थ होने लगी और जापान व यूरोप ने अपना आर्थिक विस्तार जारी रखा।

हालांकि हमारी सोच के हिसाब से उतार की गति नियंत्रित रहेगी, विकासशील देशों में परिस्थितियां कठोर भी बन सकती हैं। इनमें ये मुद्दे शामिल हो सकते हैं – यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की मंदी अधिक गहरी

साबित हुई, तो निर्यात की मांग घट सकती है और वित्तीय क्षेत्र में गड़बड़ी आ सकती है; और अगर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक वृद्धि होने लगी या असंतुलन लंबी अवधि के लिए जारी रहा, तो ऋणादान में कीमत-लागत के अंतर और इससे जुड़े जोखिम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा, गेहूँ, ज्वार तथा चावल के निम्न भंडारण के कारण इन उत्पादों की कीमत एकाएक बहुत बढ़ सकती है है, और इससे निर्धन गृहस्थियों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

- ### -

एंबार्गो खत्म होने से पहले मीडिया के सदस्यों को ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग सेन्टर में यह विज्ञप्ति मिल सकती है: <http://media.worldbank.org/secure>

पासवर्ड के लिए मान्यताप्राप्त पत्रकार यहां निवेदन कर सकते हैं: <http://media.worldbank.org/>

एंबार्गो खत्म हो जाने पर यह रिपोर्ट इंटरनेट पर यहां उपलब्ध होगी: <http://www.worldbank.org/gdf2007>
अन्य संसाधनों के लिए जाएं: www.worldbank.org/globaloutlook

wb268970

R:\andrew\gdf07\presentations\Press Release Draft May 8 As ammended by Merrel.doc
05/08/2007 3:47:00 PM